>

Title: Need to bring out a White – paper on essential components of policy followed for fixing the price of petroleum products.

**श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) अध्यक्ष महोदय,** अभी हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकॉनोमिक अफेयर में प्रस्ताव भेजा गया है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाई जायें क्योंकि यदि कीमतें नहीं बढ़ाई गयी तो तेल कंपनियों को 2007-08 में 52,162 करोड रूपए का नुकसान होगा। नुकसान की बात कह कर पेट्रोलियम मंत्रालय देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़वाना चाहता है पर वास्तविकता क्या है यह अंधेरे में है। 2007-08 वर्ष के जून तक समाप्त होने वाले तीन माहों की अवधि में देश की तेल कंपनियों के लाभांश में बढ़ोत्तरी होने के समाचार आए हैं जिसके अनुसार अप्रैल से जून के दौरान तीन माहों में इंडियन ऑयल का लाभांश 11 फीसदी, ओएनजीसी का 12 फीसदी, रिलायंस का 28 फीसदी बढ़ा है।

उपरोक्त के संदर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2007 में अप्रैल से जून के दौरान रिफायनरियों में लाभांश बढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 2006 की तुलना में 6.70 डालर प्रति बैरल से 10.70 डालर प्रति बैरल बढ़ा है। रिलाइन्स इंडस्ट्री का 12 डालर से 15.40 डालर, बीपीसीएल 5.4 डालर से 6.5 डालर, एचपीसीएल की मुंबई योजना का 8.08 डालर से 9.08 डालर बढ़ा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तेल कंपनियां कमा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पेट्रोलियम उद्योग का निरंतर विकास इस बात का साफ संकेत है कि यह उद्योग घाटे में नहीं है।

अतः मेरा आग्रह है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाए जाने से पूर्व सरकार पेट्रोलियम उद्योग के संबंध में श्वेत पत्र जारी करे जिससे मूल्य निर्धारण नीति क्रूड व गैस उत्पादन मात्रा, कंपनियों में पूंजीनिवेश, सरकारी करों की दरें और लाभांश की राशियों सहित कंपनियों में कुल अतिरिक्त बचत राशि की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख हो।